

प्रधान आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



सत्यमेव जयते

द्वितीय तल, जी एन टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: ceaxappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या Appeal / File No.	मूल आदेश नं / O.I.O. No.	दिनांक / Date:
	V2/S/EA2/BVR/2018-19	02/SUPDT/2018-19	06/08/2018

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-111-2019

आदेश का दिनांक / Date of Order:	09.05.2019	जारी करने की तारीख / Date of issue:	14.05.2019
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री कुमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित ज्ञापन मूल आदेश नं नुसार /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot/Jamnagar/Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants&Respondent :-

M/s Tamboli Castings Ltd.(100% EOU), Sidsar Road, Vartej, Bhavnagar-364060.

इस आदेश (अपील) में व्यंथित काह व्यक्त निम्नलिखित तरिके से उपयुक्त प्राधिकार / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

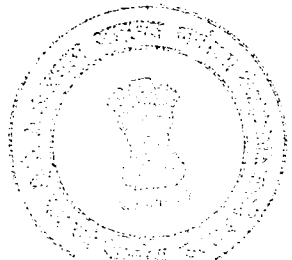
(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं
विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act,
1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गिक शुभल्योक्त समन्वयित मीमांसा मूल्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters
relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में ब्रताम राग अपीलों के अलावा श्रेय नारी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की
पश्चिम क्षेत्रीय पीठ को, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan,
Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवाली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये
प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया
जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा
10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार
के नाम में किमी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में
होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित
शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal)
Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/-
where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of
crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any
nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be
accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, विन अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित
प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उनके साथ विन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति
प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे
कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित
जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम में किमी भी सार्वजनिक
क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय
न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form
S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against
(one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest
demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is
more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs. Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty
levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated
Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by
a fee of Rs.500/-



पारित आदेश की प्रतियां संलग्न कर (उन्हे में एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिये) और आयुक्त द्वारा महायुक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आदेशित करने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी है। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the Section 86 of the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अधिनियम प्राधिकरण (सेक्टर) के प्रति अपीलीय क्र. मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विनियम अधिनियम, 1994 की धारा 80 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, एक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर माल के 10 प्रतिशत (10%) एक मात्र एक न्यूनतम विवक्षित है, या जमाना, जब तक कि न्यूनतम विवक्षित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अतिरिक्त को रकम इन कर्नेट नियम में अधिकतम हो:

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अधिनियम द्वारा 'दुर्लभ वस्तु शुल्क' में विवक्षित है
 - (ii) धारा 11 की के अंतर्गत रकम
 - (iii) न्यूनतम जमा की गई न्यूनतम रकम
 - (iii) न्यूनतम जमा नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विनियम (नं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत में पूर्व किमी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विवक्षित न्यूनतम अंजी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1994 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार कोपरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत अवर सूचित्र, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, वावत दीप भवन, नन्द मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिये। / A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1994 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किमी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने में अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह में दूसरे अंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारगृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी माल या क्षेत्र को निर्यात करने वाले माल को किसी भी देश में प्रत्येक बड़े माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिफंड) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी माल को अर्थ को निर्यात की गई है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India or on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या अंडारन को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) मुनिश्चित उत्पाद के उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए जो कर्नेट क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई नगरीय अथवा सहायविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रत्येक संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनियमित है, इस आदेश के न्यायिक के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिये। / The above application shall be made in duplicate in form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by, we comes each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिये। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त दर में किया जाना चाहिये। इन दरों के हरे हरे रूप में की लिखा पट्टी कार्य में बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of orders in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripporia work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथास्थिति न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट जमा होना चाहिये। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under sub-section 1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अधिनियम न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में बणित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाना है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबन्धित व्यय, विनियम और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



:: ORDER-IN-APPEAL ::

The Commissioner of Central GST, Bhavnagar (*hereinafter referred to as 'Department'*) filed the present appeal against Order-in-Original No. 02/SUPDT/JAM-I/2018-19 dated 6.8.2018 (*hereinafter referred as "the impugned order"*) passed by the Superintendent, Central GST & Central Excise, Range-1, Division-1, Bhavnagar (*hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"*) in respect of M/s. Tamboli Castings Ltd. (100 % EOU), Sidsar Road, Vartej, Bhavnagar (*hereinafter referred to as "Respondent"*).

2. The brief facts of the case are that the Respondent was issued Show Cause Notice No. AR-1/Audit/CRA/TCL(EOU)/17-18 dated 18.5.2018 after CERA Audit pointed that the Respondent had not paid Service Tax of Rs. 6,86,924/- on the Exhibition Service during the period from 2012-13 to 2016-17 under Section 73 of the Finance Act, 1994 (*hereinafter referred to as "the Act"*), interest under Section 75 of the Act and for imposition of penalty under Section 78 of the Act on them. The Show Cause Notice was adjudicated by the lower adjudicating authority vide the impugned order vide which the proceedings initiated against the Respondent vide the Show Cause Notice dated 18.5.2018 were dropped.

3. Being aggrieved with the impugned order, the Department preferred appeals, *inter-alia*, on the grounds that as per Section 83A of the Act relating to Power of Adjudication and Notification No. 44/2016-ST dated 28.9.2016, the Superintendent is empowered to adjudicate the Show Cause Notice involving Service Tax not exceeding rupee ten lakhs (excluding the cases relating to the taxability of services or valuation of services and cases involving extended period of limitation); that as per Section 83A of the Act and Notification No. 44/2016-ST it is clear that the Show Cause Notices involving extended period of limitation do not fall within the competency of the Superintendent. Since the extended period was invoked in the said Show Cause Notice it was required to be decided by Assistant Commissioner / Deputy Commissioner and not Superintendent, as per CBEC Circular No. 1049/37/2016-CX dated 29.9.2016.



3.1 Respondent vide their letter No. AC/2713 dated 15.4.2019 requested to pass the order as per legal position as the grounds raised by the Department pertain to the competency of adjudication by the Superintendent.

FINDINGS :-

4. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the grounds of appeal of Appeal Memorandum and written submissions made by the Respondent. The issue to be decided in the present appeal is as to whether the impugned order adjudicating Show Cause Notice invoking extended period is correct or not.

5. I find that vide CBEC vide Circular No. 1049/37/2016-CX dated 29.9.2016 clarified monetary limit of various officers for adjudication of the Show Cause Notices which reads as under :-

(ii) The above monetary limits are hereby prescribed for all categories of cases, except the following :

(a) cases of refund (including rebate) under Section 11B of the Central Excise Act, 1944, as made applicable to Service Tax cases also under Section 83 of the Finance Act, 1994, shall be adjudicated by the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner without any monetary limit.

(b) cases related to issues mentioned at Sl. No. (a) and (d) under the first proviso to Section 35B(1) of the Central Excise Act, 1944 shall be adjudicated in the following manner :

Sl. No.	Central Excise Officer	Monetary Limits for Central Excise
1.	Additional/Joint Commissioner	Exceeding Rs. 50 lakh
2.	Deputy/Assistant Commissioner	Above Rs. 10 lakh but not exceeding Rs. 50 lakh
3.	Superintendent	Not exceeding Rs. 10 lakh

(i) Cases involving taxability, classification, valuation and extended period of limitation shall be kept out of the purview of adjudication by Superintendents. Such cases, upto rupees 10 lakhs, shall also be adjudicated by the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner in addition to the cases exceeding rupees 10 lakhs but not exceeding rupees 50 lakhs.

[Emphasis supplied]

6. Section 83A of the Act relates to Power of Adjudication which is reproduced as under :-

“Section 83A. Power of adjudication. --- Where under this Chapter or the rules made thereunder any person is liable to a penalty such penalty may be adjudged by the Central Excise Officer conferred with such power as the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963) may by modification in the Official Gazette specify.”

6.1 Notification No. 44/2016-ST dated 28.6.2016 reads as under :-

Amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 30/2005-Service Tax, dated the 10th August, 2005, published vide number G.S.R. 527(E), dated the 10th August, 2005, namely :-

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :-

TABLE

Sr. No.	Rank of the Central Excise Officer	Amount of service tax or CENVAT credit specified in a notice issued under the Finance Act 1994.
(1)	(2)	(3)
(1)	Superintendent	Not exceeding rupees ten lakh (<u>excluding the cases relating to taxability of services or valuation of services and cases involving extended period of limitation</u>).
(2)	Assistant Commissioner or Deputy Commissioner	Not exceeding rupees fifty lath (except cases where Superintendents are empowered to adjudicate).
(3)	Joint Commissioner or Additional Commissioner	Rupees fifty lath and above but not exceeding rupees two crore.
(4)	Commissioner	Without limit.”

7. On conjoint reading of the above statutory provisions, it is evident that the Superintendent was/is not empowered to adjudicate any case involving extended period of limitation, even though the amount involved is less than Rs.10 lakhs. The Respondent has not disputed this legal position, as is seen from their letter dated 15.4.2019. The impugned order passed by the Range Superintendent is beyond his authority and hence, *non est* and is required to be set aside. The impugned order, is therefore, set aside and remanded for *de novo* adjudication by the competent jurisdictional adjudicating authority (i.e. Divisional Assistant Commissioner

/ Deputy Commissioner) on merits of the case, who shall pass speaking and reasoned order within three months of receipt of this order after giving reasonable and fair opportunity to the respondent to submit their case. The Respondent is directed to submit their written reply within one month to their Divisional Assistant Commissioner / Deputy Commissioner and appear before the adjudicating authority on first or second personal hearing date, as per PH notice to be sent to them by Speed Post.

8. In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal by way of remand to be decided on merit by the jurisdictional Divisional Assistant Commissioner or Deputy Commissioner, as the case may be, within 3 months from receipt of this order as directed above.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The Appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.

(कुमार संतोष)

प्रधान आयुक्त (अपील्स)

By R.P.A.D.

To,

1. The Commissioner,
Central GST & C. Excise,
Bhavnagar Commissionerate,
Bhavnagar.

2. M/s. Tamboli Castings Ltd. (100 % EOU),
Sidsar Road,
Vartej, Bhavnagar.

प्रति :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल - 1, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) गार्ड फाइल।

